AMOGHVARTA
ISSN : 2583-3189

विकसित भारत के निर्माण में डिजिटल संचार

ORIGINAL ARTICLE

Author
डॉ. अनिल कुमार शुक्ला
वरिष्ठ एसोसिएट प्रोड्यूसर
IBC 24 न्यूज़
रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

किसी देश का विकास उस देश में रहने वाले मानव जाति के विकास पर निर्भर होता है। मानव जाति का विकास उसके वातावरण, रहन–सहन, खान–पान, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी और मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर तय किया जाता है। मनुष्य के संपूर्ण विकास में खासकर चार "स" महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर एक स्वास्थ्य, नंबर दो शिक्षा, नंबर तीन सुविधाएं और नंबर चार संचार। मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए स्वास्थ्य, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, आर्थिक विकास के लिए मूलभूत सुविधाएं और सामाजिक विकास के लिए संचार बहुत ही जरूरी है। अगर यह चार चीजें किसी भी व्यक्ति को सुलभ हो जाएं तो वह व्यक्ति अपनी जरूरत के मुताबिक तमाम संसाधन और उपभोग की वस्तुएं एकत्रित कर सकता है। वर्तमान समय में सुख, शांति, समृद्धि और सुविधाओं से परिपूर्ण समाज को ही विकसित समाज माना जाता है। विकसित देश को भी इसी संदर्भ में लिया जा सकता है, अर्थात् जहां का मानव समाज विकसित हो, जहां मनुष्य के लिए तमाम जरूरी सुविधाएं सुलभ हों, जहां मनुष्य खुश रहकर शांतिपूर्वक और सुविधाओं से युक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करता हो।

मुख्य शब्द

डिजिटल संचार, विकसित भारत, डिजिटल संचार माध्यम, डिजिटल मीडिया, विकास संचार.

प्रस्तावना

मनुष्य के विकास में संचार एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। मनुष्य के जन्म के साथ ही संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक विभिन्न रूपों में संचार होता रहता है। मनुष्यों के बीच संचार के लिए पारंपरिक रूप से कई संचार साधन विद्यमान रहे हैं और क्रमशः इनका विकास भी होता रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि संचार माध्यमों पर जिस देश का जितना आधिपत्य और पहुंच रही है, वह देश उतनी ही तीव्र गति से विकसित होता गया। दुनिया के तमाम देशों को विकसित बनाने में संचार माध्यमों का अमूल्य योगदान रहा है।

डिजिटल संचार ने 21वीं सदी में भारत के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। आज यह शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, प्रशासन और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। डिजिटल संचार तकनीकों ने न केवल सूचना और सेवाओं की पहुंच को सुगम बनाया है, बल्कि सरकारी योजनाओं और नीतियों के प्रभावी

क्रियान्वयन में भी सहायता की है। वर्तमान समय की बात करें तो मनुष्य के जीवन में इस अवधि में डिजिटल संचार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। डिजिटल संचार का प्रभाव न सिर्फ एक ''जन'' तक सीमित है बल्कि इसका प्रभाव अब ''जनता'', ''जनप्रतिनिधि'' से लेकर ''जनतंत्र'' तक परिलक्षित हो रहा है।

डिजिटल संचार माध्यम

डिजिटल संचार माध्यम उन तकनीकों और प्लेटफार्मों को संदर्भित करता है जो डिजिटल तकनीक का उपयोग करके सूचना के आदान–प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं। डिजिटल संचार माध्यम ने संचार की प्रक्रिया को सरल, तीव्र, प्रभावशाली और व्यापक पहुंच प्रदान करने वाला बना दिया हैं। हालाँकि, इसके प्रभावी और सुरक्षित उपयोग के लिए उचित सावधानियाँ बरतना आवश्यक है। कुछ डिजिटल संचार माध्यम इस प्रकार हैं।

1. **सोशल मीडियाः** जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब आदि जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक संचार के लिए उपयोग किया जाता है।
2. **ई–मेलः** औपचारिक और अनौपचारिक संचार के लिए प्रमुख माध्यम, जैसे कि जीमेल, याहू मेल, आउटलुक आदि।
3. **मोबाइल संचारः** त्वरित संदेश और वॉयस/वीडियो कॉल के लिए, जैसे कि एसएमएस, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे प्लेटफार्म।
4. **वेबसाइट और ब्लॉगः** व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी साझा करने के लिए, जैसे कि सूचना प्रसार और डिजिटल मार्केटिंग के लिए प्रमुख माध्यम।
5. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगः** दूरस्थ कार्य, शिक्षा और व्यवसायिक बैठकों के लिए, जैसे कि ज़ूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे प्लेटफॉर्म।
6. **पॉडकास्ट और वेबिनारः** शैक्षिक, मनोरंजन और व्यावसायिक जानकारी प्रसारित करने के लिए, जैसे कि ऑडियो आधारित डिजिटल संचार माध्यम।
7. **ऑनलाइन समाचार पोर्टलः** त्वरित और व्यापक समाचार वितरण के लिए, जैसे कि डिजिटल समाचार वेबसाइटें, बीबीसी हिंदी, आजतक, नवभारत टाइम्स, लाइव हिदुस्तान, एनडीटीवी आदि।

डिजिटल संचार माध्यम के लाभ

डिजिटल संचार माध्यमों के जरिए मनुष्य को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। पहला तेजी और सुलभता, सूचना तुरंत भेजी और प्राप्त की जा सकती है, दूसरा व्यापक पहुंच, ग्लोबल स्तर पर लोगों तक पहुंच बनाई जा सकती है। तीसरा प्रभावी लागत, पारंपरिक संचार की तुलना में कम खर्चीला होता है, चौथा संग्रहण और विश्लेषण, डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है और विश्लेषण किया जा सकता है।

देश के विकास में डिजिटल संचार की भूमिका

देश के सर्वांगीण विकास में डिजिटल संचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ हुआ है और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था, शासन, शिक्षा और सामाजिक विकास के विभिन्न पहलुओं को सशक्त बनाता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, जो 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था, उसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है।

डिजिटल संचार ने आवश्यक दस्तावेज़ों के निर्माण, उपलब्धता और प्रबंधन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं। डिजिटल सेवाओं ने दस्तावेज़ निर्माण, प्रबंधन और वितरण की प्रक्रियाओं को अधिक कुशल, पारदर्शी और सुलभ बनाया है, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी हुई है। इसकी भूमिका निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में देखी जा सकती हैः

1. **ई–गवर्नेंस और सरकारी सेवाएंः** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर लाया गया है, जिससे नागरिकों को सेवाओं का त्वरित और पारदर्शी लाभ मिल रहा है। सरकारी

सेवाएँ अब ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से वास्तविक समय में उपलब्ध हैं, जिससे नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज़ों के लिए आवेदन और प्राप्ति में सुविधा हुई है। डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता मिलने से दस्तावेज़ों के इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण में सुविधा हुई है, जिससे कानूनी प्रक्रियाएँ अधिक सुरक्षित और तेज़ हो गई हैं। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग ई–गवर्नेंस, व्यावसायिक अनुबंधों और बैंकिंग लेन–देन में व्यापक रूप से हो रहा है।

2. **आर्थिक विकासः** डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान 2022–23 में राष्ट्रीय आय का 11.74: था, जो लगभग 31.64 लाख करोड़ रुपये (लगभग 402 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के बराबर है। यह संकेत देता है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और भौतिक क्षेत्रों के डिजिटलीकरण के माध्यम से अर्थव्यवस्था के सभी हिस्सों में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रसार हो रहा है। ई–कॉमर्स, फिनटेक और आईटी सेवाओं के माध्यम से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) जैसे प्लेटफ़ॉर्म छोटे व्यवसायों को डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने में सहायता कर रहे हैं।
3. **ग्रामीण विकासः** सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए ई–नाम पोर्टल जैसी पहलों के माध्यम से कृषि विपणन को सरल और पारदर्शी बनाया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है।
4. **शिक्षा और जागरूकताः** डिजिटल संचार माध्यमों ने ऑनलाइन शिक्षा, वेबिनार और डिजिटल पुस्तकालयों के माध्यम से शिक्षा को सुलभ बनाया है, जिससे ज्ञान का व्यापक प्रसार संभव हुआ है। डिजिटल प्रौद्योगिकी ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुंच मिलती है।
5. **सामाजिक संपर्क और जागरूकताः** सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स ने लोगों को जोड़ने, विचारों का आदान–प्रदान करने और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स से लोगों के बीच संवाद में वृद्धि हुई है। डिजिटल संचार माध्यमों ने कला, संस्कृति और भारतीय विरासत के प्रचार–प्रसार को भी बढ़ावा दिया है।
6. **डिजिटल अवसंरचना का विस्तारः** भारतनेट जैसी परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हाई–स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई कम हो रही है।
7. **डिजिटल कौशल विकासः** डिजिटल कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए, स्किल इंडिया डिजिटल हब ने 1 करोड़ से अधिक पंजीकरण प्राप्त किए हैं, जिससे उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए तैयार कार्यबल तैयार हो रहा है।
8. **स्मार्टफोन और इंटरनेट का प्रसारः** किफायती स्मार्टफोन और सस्ते डेटा प्लान्स ने भारत को मोबाइल–प्रथम डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदल दिया है, जिससे ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान और मनोरंजन तक पहुंच बढ़ी है। मोबाइल सेवाओं के माध्यम से भी नागरिकों तक सरकारी सूचनाएँ और सेवाएँ पहुँचाई जा रही हैं। एसएमएस गेटवे के माध्यम से सरकार नागरिकों को पुश और पुल एसएमएस सेवाएँ प्रदान करती है, जिससे वे आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
9. **स्टार्टअप इकोसिस्टम और नवाचारः** भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम डिजिटल नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान ने नागरिकों को सरकारी सेवाओं से जोड़ने में मदद की है। स्टार्टअप और ई–कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स ने छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं।
10. **डिजिटल भुगतानः** डिजिटल इंडिया और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) जैसी पहलों ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया है, जिससे आर्थिक लेन–देन में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ी है। यह कदम आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हुआ है। डिजिटल भुगतान प्रणाली (जैसे, UPI, RuPay, Paytm) से कैशलेस

अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है।

11. **डिजिटल पहचान और प्रमाणनः** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान की गई है, जो जीवनभर मान्य है। यह पहचान दस्तावेज़ों की प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सरल और तेज बनाती है। हर व्यक्ति के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, श्रमकार्ड, राशनकार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खसरा, खतौनी जैसे जमीन के दस्तावेज डिजिटली रूप से ऑनलाइन बनवाना और प्राप्त करना आसान हो गया है। सभी सरकारी दस्तावेज़ और प्रमाण पत्र अब क्लाउड पर उपलब्ध हैं, जिससे नागरिक कहीं से भी और कभी भी उन्हें एक्सेस कर सकते हैं।
12. **कानून एवं व्यवस्था का संचालनः** डिजिटल संचार ने भारत में कानून एवं व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएँ अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुलभ हुई हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, सरकार ने ई–शासन को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं, जिससे नागरिक सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध हो सकें और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आए। आधार, UPI, और डिजिलॉकर जैसी सुविधाओं ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सरल बनाया है।

इस प्रकार, डिजिटल संचार भारत के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है, जो देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर कर रहा है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं भारत का विकास

पिछले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था काफी तेज गति से डिजिटल हो रही है। आर्थिक वृद्धि, रोजगार और सतत विकास को आगे बढ़ाने में डिजिटल अर्थव्यवस्था की भूमिका को मापना और समझना नीति निर्माताओं और निजी क्षेत्र दोनों के लिए आवश्यक है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 के अनुसार, अर्थव्यवस्था–वार डिजिटलीकरण के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल देश है और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के डिजिटलीकरण के स्तर में जी20 देशों में 12वें स्थान पर है।

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के समग्र अर्थव्यवस्था की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ने की उम्मीद है, जो 2029–30 तक राष्ट्रीय आय में लगभग पांचवें हिस्से के बराबर योगदान देगी। इसका मतलब है कि छह साल से भी कम समय में, देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा कृषि या विनिर्माण से ज्यादा हो जाएगा। अल्पावधि में सबसे अधिक वृद्धि डिजिटल इंटरमीडियरीज और प्लेटफार्मों के विकास से आने की संभावना है, इसके बाद बाकी अर्थव्यवस्था का ज्यादा डिजिटल प्रसार और डिजिटलीकरण होगा। इससे अंततः डिजिटल अर्थव्यवस्था में डिजिटल रूप से सक्षम आईसीटी उद्योगों की हिस्सेदारी कम हो जाएगी।

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था इसकी आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले के रूप में उभरी है, जिसकी 2022–23 में जीडीपी (31.64 लाख करोड़ रुपये या 402 बिलियन अमेरिकी डॉलर) में 11.74 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। 14.67 मिलियन श्रमिकों (कार्यबल का 2.55 प्रतिशत) को रोजगार देने वाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बाकी अर्थव्यवस्था की तुलना में लगभग पांच गुना अधिक उत्पादक है। आईसीटी सेवाओं और मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक घटकों, कंप्यूटर और संचार उपकरणों के विनिर्माण जैसे डिजिटल रूप से सक्षम उद्योगों ने जीवीए (सकल मूल्य वर्धित) में 7.83 प्रतिशत का योगदान दिया, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरमीडियरीज ने जीवीए में 2 प्रतिशत योगदान दिया है। इसके अलावा, बीएफएसआई, खुदरा और शिक्षा जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में डिजिटलीकरण ने जीवीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि की, जो डिजिटल परिवर्तन के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। अनुमानों से संकेत मिलते हैं कि 2029–30 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी जीवीए के 20 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, जो कृषि और विनिर्माण से आगे निकल जाएगी।

शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल संचार का योगदान

भारत में शिक्षा के विकास में डिजिटल संचार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे अध्ययन और सीखने की प्रक्रिया अधिक सुलभ, लचीली और समावेशी बनी है। इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच ने छात्रों को पारंपरिक कक्षाओं के बाहर भी शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। डिजिटल संचार के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैः

1. **लचीलापन और सुविधाः** छात्र अब अपनी सुविधा के अनुसार समय और स्थान पर अध्ययन कर सकते हैं, जिससे शिक्षा अधिक व्यक्तिगत और अनुकूलित हो गई है।
2. **इंटरएक्टिव और आकर्षक सामग्रीः** वीडियो, एनिमेशन और क्विज़ जैसे मल्टीमीडिया तत्वों के समावेश से सीखना अधिक रोचक और प्रभावी हुआ है। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफ़ॉर्म्स (जैसे, SWAYAM, Diksha, Byju's) और डिजिटल पुस्तकालयों के माध्यम से शिक्षा का प्रसार हुआ है, जिससे छात्रों और पेशेवरों को नई कौशल सीखने और ज्ञान अर्जित करने में सहायता मिली है।
3. **विविध संसाधनों तक पहुंचः** ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से छात्रों को विभिन्न विषयों पर विस्तृत सामग्री उपलब्ध होती है, जिससे उनका ज्ञानवर्धन होता है। डिजिटल क्लासरूम और ई–लर्निंग से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की शैक्षिक खाई कम हो रही है।
4. **सरकारी पहलः** भारत सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जैसे कि ''स्वयं'' (SWAYAM), यह एक विशाल ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOC) पहल है, जिसका उद्देश्य उच्च माध्यमिक से स्नातक स्तर तक के पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध कराना है, ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र भी शिक्षा से जुड़ सकें। ''स्वयं प्रभा'' (SWAYAM Prabha), यह 32 डीटीएच चैनलों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री प्रसारित करता है, जिससे इंटरनेट की कमी वाले क्षेत्रों में भी शिक्षा पहुंचाई जा सकती है।

जाहिर है कि डिजिटल संचार ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, लेकिन इसके पूर्ण लाभ के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार, डिजिटल साक्षरता का प्रसार और सभी के लिए तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में डिजिटल संचार का योगदान

स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल संचार ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच, गुणवत्ता और दक्षता में सुधार हुआ है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और रोगियों के बीच संचार को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख घटक इस प्रकार हैंः

1. **टेलीमेडिसिनः** टेलीमेडिसिन के माध्यम से रोगी दूरस्थ स्थानों से ही चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है। COVID–19 महामारी के दौरान, टेलीमेडिसिन की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है, जिससे मरीजों को घर बैठे ही चिकित्सा सेवाएँ मिल सकीं। टेलीमेडिसिन और ई–हेल्थ सेवाएं (जैसे, ई–संजीवनी) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की पहुंच बढ़ा रही हैं।
2. **मोबाइल स्वास्थ्य (mHealth):** मोबाइल एप्लिकेशनों और पहनने योग्य उपकरणों के माध्यम से स्वास्थ्य निगरानी, दवा अनुस्मारक और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे रोगी अपनी सेहत पर निगरानी रख सकते हैं।
3. **इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (EHR):** EHR सिस्टम के जरिए रोगियों के स्वास्थ्य डेटा का डिजिटल रूप में संग्रहण और साझा करना संभव होता है, जिससे चिकित्सकों को सटीक और त्वरित जानकारी मिलती है। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स और आरोग्य सेतु जैसे ऐप स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में सहायक हैं।
4. **ई–हॉस्पिटल और ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ORS):** ई–हॉस्पिटल एप्लिकेशन अस्पतालों के आंतरिक कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करता है, जबकि ORS मरीजों को ऑनलाइन पंजीकरण और अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है।

5. **राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (टेली मानस):** यह कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य परामर्श अधिक सुलभ हो गया है।

इस प्रकार से डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के कई लाभ सामने आए हैं जैसे बेहतर पहुँच, दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में वृद्धि होती है। इसके अलावा लागत में कमी भी एक बड़ा लाभ है, टेलीमेडिसिन और डिजिटल उपकरणों के उपयोग से स्वास्थ्य सेवा की लागत में कमी आती है, जिससे यह अधिक वहनीय होती है। साथ ही व्यक्तिगत देखभाल संभव हुआ है, डिजिटल उपकरणों के माध्यम से मरीज अपनी स्वास्थ्य जानकारी तक पहुँच सकते हैं, जिससे वे अपनी सेहत के प्रति अधिक जागरूक और सक्रिय हो सकते हैं।

कुल मिलाकर, डिजिटल संचार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, लेकिन इन सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बुनियादी ढाँचे की मजबूती, डिजिटल साक्षरता में वृद्धि और डेटा सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में डिजिटल संचार

भारत में डिजिटल संचार ने बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, जिससे नागरिकों को सेवाएँ अधिक सुलभ, पारदर्शी और कुशलता से प्राप्त हो रही हैं। देश में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, आधार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम है, जिसने 138.34 करोड़ से अधिक नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की है। यह पहचान सरकारी सेवाओं तक पहुँच को सरल और सुरक्षित बनाती है। इसी प्रकार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) ने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया है, जिससे वित्तीय समावेशन में वृद्धि हुई है; 30 जून 2024 तक, यूपीआई के माध्यम से 24,100 करोड़ लेनदेन संपन्न हुए हैं।

सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति–2018 का उद्देश्य एक सर्वव्यापी, लचीली, सुरक्षित, सुलभ और किफायती डिजिटल संचार अवसंरचना की स्थापना के माध्यम से नागरिकों और उद्यमों की सूचना और संचार सम्बंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसी प्रकार राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति–2018 का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को 50 मेगाबिट प्रति सेकंड (Mbps) की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय फाइबर प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना की योजना बनाई गई थी, जिससे डिजिटल संचार अवसंरचना में सुधार हो सके। इन पहलों के माध्यम से, डिजिटल संचार ने भारत में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किया है, जिससे नागरिकों का जीवन अधिक सुविधाजनक और समृद्ध हुआ है।

डिजिटल संचार के माध्यम से पत्रकारिता

डिजिटल संचार तकनीक ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी नए अवसर और चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं, जिससे समाचारों का प्रसार और संग्रहण अधिक प्रभावी हुआ है।

डिजिटल मीडिया ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन और प्रगति का माध्यम बना है। यह न केवल सूचना के प्रसार में तेजी लाया है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव डाला है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

1. **सूचना का त्वरित प्रसार और जागरूकता:** डिजिटल मीडिया ने जनता को त्वरित और सुलभ सूचना उपलब्ध कराई है, जिससे जागरूकता में वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप ने लोगों को वास्तविक समय में समाचार और घटनाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2. **स्वतंत्र पत्रकारिता और वैकल्पिक मीडिया:** डिजिटल मीडिया ने स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा दिया है,

जिससे वैकल्पिक समाचार स्रोतों का उदय हुआ है। यह कदम मीडिया की बहुलता और लोकतांत्रिक संवाद को सशक्त बनाता है। वर्तमान समय में यह भी देखा गया है कि सोशल मीडिया में वायरल खबरों और वीडियो पर त्वरित गति से शासन प्रशासन का ध्यान जाता है और उस पर एक्शन होता है।

चुनौतियाँ और समाधानः हालांकि, डिजिटल मीडिया के साथ फर्जी समाचार और भ्रामक जानकारी का प्रसार एक गंभीर चुनौती है। डिजिटल संचार का दायरा विस्तृत हुआ है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैंः

- **डिजिटल डिवाइडः** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल पहुंच में असमानता।
- **साइबर सुरक्षाः** डेटा सुरक्षा और साइबर अपराध बढ़ रहे हैं।
- **तकनीकी साक्षरताः** डिजिटल तकनीकों की जानकारी और उपयोगिता में कमी।

इसके समाधान के लिए सटीक और तथ्यात्मक सामग्री की आवश्यकता है, ताकि समाज में गलतफहमियों को रोका जा सके जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, साइबर सुरक्षा नीतियों को मजबूत करना, डिजिटल साक्षरता अभियानों का विस्तार।

निष्कर्ष

समग्र रूप से, डिजिटल मीडिया ने भारत के विकास में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध हुआ है। डिजिटल संचार भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण आधारशिला बन चुका है। यह प्रशासन को पारदर्शी, शिक्षा को सुलभ, स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी, और अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना रहा है। यदि इसके समुचित उपयोग और विस्तार पर ध्यान दिया जाए, तो यह ''विकसित भारत'' के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा।

संदर्भ सूची

1. india.gov.in, Accessed on 16/03/2025.
2. PIB.GOV.IN, Accessed on 20/03/2025.
3. egovernance.vikaspedia.in, Accessed on 23/03/2025.
4. NHRC.NIC.IN, Accessed on 27/03/2025.
5. shaharparikrama.in, Accessed on 22/03/2025.
6. ddnews.gov.in, Accessed on 22/03/2025.
7. HI.WIKIPEDIA.ORG, Accessed on 26/03/2025.
8. ORFONLINE.ORG, Accessed on 20/03/2025.
9. TESTBOOK.COM, Accessed on 28/03/2025.
10. observerdawn.com, Accessed on 01/04/2025.
11. TV9HINDI.COM, Accessed on 23/03/2025.
12. NEXTIAS.COM, Accessed on 25/03/2025.
13. DRISHTIIAS.COM, Accessed on 04/04/2025.
14. babushahihindi.com, Accessed on 17/03/2025.
15. prativad.com, Accessed on 05/05/2025.
16. truenewsup.com, Accessed on 05/05/2025.
17. apnimaati.com, Accessed on 02/05/2025.
18. ANYTIMENEWS.LIVE, Accessed on 16/03/2025.

——==00==——